

संक्षिप्त समाचार

पीडीए पाठशाला को जनआंदोलन में

बदलने का आह्वान
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 'पीडीए पाठशाला' के संकेतिक आंदोलन को अब वास्तविक और जमीनी जनआंदोलन में बदलना होगा। तभी शांति-वॉचन समाज को आने वाली पीढ़ियों पर-लिखकर आगे बढ़ सकेगी। उन्होंने आपग लगाया कि भाजपा की शिक्षा-विरोधी सोच के कारण प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि भाजपा जानती है कि शिक्षा से लोगों में जागरूकता और वैज्ञानिक चेतना आती है, जो उसकी दकृष्टिगति, हिंसावादी और संकीर्ण सोच के लिए खतरा है। इसी वजह से भाजपा शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान के खिलाफ खड़ी है और उसके मंत्री-साथी बच्चों को एकदली नकारात्मक विचारधारा में डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों से शिक्षा और तालीम का अधिकार छीना एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पीडीए समाज को ही उठाना पड़ेगा।

योगी ने लता को पुरोहितिय पर टी विमन श्रद्धांजलि
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय योगी आचार्यसंघ के भारतीय योगी को अपनी दिव्य स्वर-नाथान में विरच पटल पर प्रतिष्ठित करने वाली स्वर कोकिला, 'भारत रत्न' लता मंगेशकर की पुरोहितिय पर उच्च विमन श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लता मंगेशकर का आध्यात्मिक गान और संगीत के प्रति उनका आजीवन समर्पण कला जगत के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनकी मधुर गायी और संगीत सामना सर्वत्र हमारे हृदयों में जीवंत रहेगा तथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।

	सेलैस 83580.40
	लोना 151489
	चांदी 25693.70
	प्रो 10 खान (2 कैरेट)

एफएमसीजी, निजी बैंकों में लिवाली से चढ़े प्रमुख सूचकांक

मुंबई, वार्ता
भारत सरकार ने शुक्रवार को एफएमसीजी और निजी बैंकों के शेयरों में तेजी रही और प्रमुख सूचकांक हर निशान में बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 266.47 अंक (0.32 प्रतिशत) ऊपर 83,580.40 पर चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निप्पेटी-50 सूचकांक भी 50.90 अंक बढ़कर 25,693.70 पर चढ़ गया था। सुबह संसेक्स एक समय 388 अंक टूट गया था, लेकिन रिजर्व बैंक (आरबीवी) के नीतिगत नीति बयान से उत्साहित निवेशकों की लिवाली से दोपहर बाद लिवाली से यह 288 अंक चढ़

प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति मनोबल टूटने पर ही बोलेगा अपशब्द

नई दिल्ली, वार्ता
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति यदि अपशब्द और अस्वच्छ बोलने लगता है, तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि उन्हें कोई हवाशा है, जिसके कारण उनका मनोबल टूट गया है। खड्गे ने प्रधानमंत्री के राज्यस्था में राष्ट्रपति के अधिभाषण पर धनवाद प्रस्ताव पर शुक्रवार को दिए गए जवाब पर एक वीडियो पोस्ट में शुक्रवार को कहा कि मोदी ने 97 मिनिट पर अपना भाषण दिया और इसमें वह सच असत्य ही दोहराते रहे हैं। जब हमने अधिभाषण पर अपनी बातें रखीं उनका भी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ 100 साल, 75 साल, 50 साल की बात करते हैं। इसका मतलब यही है कि मोदी के पास हमारे पूरे राष्ट्र के जवाब देने की शक्ति ही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी कांग्रेस पर अश्लील श्रमण करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सी मोदी ने सिखा का आदर करते हैं, न

यूपी में दावे व आपत्तियों की तारीख एक महीने बड़ी

लखनऊ, वार्ता
यूपी में एसआईआर पर दावे और आपत्तियों की तारीख एक महीने तक बढ़ा दी गई है। अब 6 फरवरी की जगह 6 मार्च तक फॉर्म-6 और फॉर्म-7 जमा करवाया जा सकता है। नॉटिस की सुनवाई को प्रक्रिया 27 मार्च तक चलेगी, इसके बाद 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहाल मतदान सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिग्वा ने बताया कि प्रदेश में 27 अक्टूबर को एसआईआर की प्रक्रिया को शुरूआत की गई थी। घर-घर जाकर बीएलओ की तरफ से गणना का काम 4 नवंबर से शुरू किया गया था, कुछ 6 जनवरी को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया गया था। नवंबर रिग्वा ने बताया कि जनांकित तरीके और नगरपालिका की अपील पर चुनाव आयोग ने समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमारा लक्ष्य है कि मतदाता सूची पूरी तरह से सटीक और समावेशी बने। पहले लखनऊ की अवधि 6 फरवरी में समाप्त हो रहा था, लेकिन अब यह मार्च तक बढ़ा दिया गया है। विसंगतियों या नॉटिस के जवाब का निपटारा 27 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। विदेश में रहे रह नागरिक भी फॉर्म 6। प्रकर मतदाता सूची में नाम जुड़ना सकते हैं। नवदीप रिग्वा ने कहा कि प्रदेश में देश की सबसे बड़ी मतदाता संख्या है। यहां लगभग 15 करोड़ से अधिक वोट हैं। एसआईआर 2026 की प्रक्रिया पिछले साल से चले रही है। एसआईआर का उद्देश्य पुरानी सूचियों से लिकिन, डुप्लीकेट नाम हटाना और नई एंट्रीज को सुनिश्चित करना है।

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगसत साल से होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर उपरले विरोधी सुरों ने पार्टी नेतृत्व को निता बढ़ा दी है। जनजातिनिधियों बनाम अधिभाषण और सरकारी बनाम संगठन के बीच खिचती रेखा अब सार्वजनिक बहस का विषय बनती जा रही है। 30 जनवरी को महोबा में जल शक्ति मंत्रालय देह सिंह और स्थानीय भाजपा विधायक बृजगोपा रावपुत्र के बीच बहसक पर हुआ सीधा विवाद इसी अंतर्निर्गत का ताजा उदाहरण माना जा रहा है। हालांकि पट्टी नेतृत्व ने इसे मामूली टकराव बताया, लेकिन विवासी पीछले में इस सार और संयोजन के बीच आने वाली एक

शाह टाइम्स ब्यूरो

कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। महोबा में जल शक्ति मंत्री देह सिंह देह सिंह और भाजपा विधायक बृजगोपा रावपुत्र के बीच हुई तीनों लोकसभा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा मामला पार्टी के संज्ञान में है। इस मामले में दोनों नेताओं से बात कर दी गई है। हालांकि वह पहला मौका नहीं है जो भाजपा के भीतर अनुरासन के बीच बयान में टकरा दिखाई दी हो। बतें कुछ वक्त में ऐसे कई प्रसंग सामने आए हैं, जब जनजातिनिधियों की महत्वाकांक्षा और प्रशासनिक कार्यशैली के

‘घूसखोर पंडत’ पर लगे प्रतिबंध: मायावती

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बंब सीट पर 'घूसखोर पंडत' में 'पंडित' शब्द को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर कोड़ा ऐताराज बताया है। उन्होंने इसे बेहद दुखद और विताजनक बतते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब किल्यों के माध्यम से भी एक विशेष वर्ग को अपमान किया जा रहा है, जिससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि फिल्म में 'पंडित' को 'घूसपंडित' बताया कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जातिव्यवस्था टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को



नुकसान पहुंचाने वाली है और इन्हें किसी भी सूत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बरपा प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनको पार्टी इस तरह की टिप्पणी को कड़ी निन्दा करती है। उन्होंने कंड सरकारी से मांग की कि ऐसी जातिव्यवस्था और समाज को बांटने वाली फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि सामाजिक न्याय को रक्षा जा सके। मायावती ने कहा कि संविधान सभी वर्गों को समान और समता का अधिकार देता है, ऐसे में किसी भी माध्यम से किसी समाज को

पदाधिकारियों को अहम बैठक आज

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को पार्टी संघटन की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के विपक्ष पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। बैठक से पूर्व मायावती मीडिया को संभावित करींगीं।

अपमानित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि कानून-व्यवस्था को सामाजिक समरता के लिए भी धाक है। उन्होंने कंड सरकारी से मांग की कि ऐसी जातिव्यवस्था और समाज को बांटने वाली फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि सामाजिक न्याय को रक्षा जा सके। मायावती ने कहा कि संविधान सभी वर्गों को समान और समता का अधिकार देता है, ऐसे में किसी भी माध्यम से किसी समाज को

विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटे चुनाब से पूर्व यूपी भाजपा में अंतर्विरोधों की आहट

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगसत साल से होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर उपरले विरोधी सुरों ने पार्टी नेतृत्व को निता बढ़ा दी है। जनजातिनिधियों बनाम अधिभाषण और सरकारी बनाम संगठन के बीच खिचती रेखा अब सार्वजनिक बहस का विषय बनती जा रही है। 30 जनवरी को महोबा में जल शक्ति मंत्रालय देह सिंह और स्थानीय भाजपा विधायक बृजगोपा रावपुत्र के बीच बहसक पर हुआ सीधा विवाद इसी अंतर्निर्गत का ताजा उदाहरण माना जा रहा है। हालांकि पट्टी नेतृत्व ने इसे मामूली टकराव बताया, लेकिन विवासी पीछले में इस सार और संयोजन के बीच आने वाली एक



कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। महोबा में जल शक्ति मंत्री देह सिंह देह सिंह और भाजपा विधायक बृजगोपा रावपुत्र के बीच हुई तीनों लोकसभा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा मामला पार्टी के संज्ञान में है। इस मामले में दोनों नेताओं से बात कर दी गई है। हालांकि वह पहला मौका नहीं है जो भाजपा के भीतर अनुरासन के बीच बयान में टकरा दिखाई दी हो। बतें कुछ वक्त में ऐसे कई प्रसंग सामने आए हैं, जब जनजातिनिधियों की महत्वाकांक्षा और प्रशासनिक कार्यशैली के

लेकर असंतोष खुलकर सामने आया। इससे पहले जुलाई 2022 में जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक द्वारा अधिकारियों पर उपेक्षा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देना, इसी वैचैनी का बड़ा संकेत था। हालांकि बाद में मामला संभाल लिया गया, लेकिन तब वह संदेश साफ चला गया कि अंदरूनीर सब कुछ ठीक नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी के भीतर कलह खुलकर सामने आई थी। मुजफ्फरपुर सीट से चुनाब लड़ रहे केंद्रीय मंत्री डा. संजीव बालियान और भाजपा के पूर्व विधायक सीरीत साठे के बीच

खींचतान खुलकर आने लगी सामने
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सत्ताधारी भाजपा के भीतर की नहीं, बल्कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के मंत्रियों के बीच भी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। ताना माहला कीकेंचने में ही आम प्रकाश रावत और अमिल रावत के बीच बढ़ती टकराव का है, जो अब सार्वजनिक मंचों तक पहुंच चुका है। दोनों नेम ने सिर्फ एक ही बात से आते हैं, बल्कि एक ही इलाक के निवासी हैं और योगी सरकार में केंद्रित स्तर के मंत्री भी हैं। इससे समझ से चलती जा रही आपसी अलगाव और वैचैनी बयानबाजी में बदलती दिख रही है। जब निजी पत्रकार अमिल रावत एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी सीमा गणना करने कुछ लोगों ने सारेकाजी शुरू कर दी। इससे नावज की अंतिम रावत ने नांबाजी कर के आरोप लगाते हुए प्रकाश रावत का सार्वजनिक बतते हुए कहा कि बेनाम इनाफा नते बाते हैं, जैसे ये भी बाते हैं। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आम प्रकाश रावत ने अमिल रावत पर एतवार बतते हुए कहा कि उनका उद्देश्य नते बतते 23 साल पहले लोहे की दुकान चलते थे और चोर की बतें।

चली तीखी बजाबी जंग का असर कई सीटों पर पड़ा। चुनाव परिणाम आने के बाद हारावतुर से भाजपा प्रत्याशी रावत लखनवात शर्मा ने खुले तरीे पर अलगाव की घटना पार्टी के ही मंत्री और विधायक वाम आरोग लगाकर सियासी ताम्राम

और बढ़ा दिया।

काम कोर्स उसस क्यों?
अधिक संख्या में हेल्थकेयर पार्ष्व शीपमन, नुसुलान, बरबन की गुलुतिों से हल्ला के लिए हुकुमारी।
फोन कर घर बैठे औषधियां डाक द्वारा प्राप्त करें।
कृषि इंटरनेशनल
08899787114
09808917010

अर्थव्यापार देश

चांदी सस्ती, सोना भी 1.51 लाख पर आया

नई दिल्ली। सोने-चांदी के दाम में 6 फरवरी को गिरावट देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजे) के अनुसार सरफा बाजार में चांदी की कीमत आज 13,155 रुपए गिरकर 2,411.84 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,54,339 रुपए थी। दो दिन में ये 41,278 रुपए सस्ती हो चुकी है। वहीं 10 ग्राम चांदी सोने का भाव आज 1,013 रुपए कम होकर 1,51,489 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,52,500 रुपए पर था। सोना दो दिन में 6,669 रुपए सस्ता हुआ है। सरफा बाजार में सोने ने 29 जनवरी को 1,76,121 और चांदी ने 3,85,935 रुपए का आल्ट हाइड बनाया था। सोने-चांदी की बढ़ती-घटती कीमतों पर न केवल निवेशकों की नजर है, बल्कि शादी-व्याह के सीजन के बीच आज खरीदारों में खरीदारी पर भी फोकस लूटी देखी गई है। हालांकि निवेशकों ने खरीदारी पर भी मुकाबला किया है। आज लखनऊ में सोने की कीमत की बात करें तो 24 कैरेट सोने का दाम 1,52,400 रुपए/10 ग्राम चल रहा है। 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,800 रुपए/10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम 1,14,310 रुपए/10 ग्राम चल रहा है। वहीं, भारपुत्र में 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,400 रुपए/10 ग्राम चल रहा है।

चांदी रु. 241184

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

प्रति किलो

[illegible]

बढ़ा समय

शुक्रवार को उग्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा कि अब दस अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। जोकि पहले 6 मार्च को होनी थी। उनका कहना था कि ऐसा मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस तरह दावा-आपत्ति की अवधि एक माह बढ़ाकर 6 मार्च तक कर दिया गया है। वहीं मैपिंग से जुड़े सभी कार्यों की प्रक्रिया 27 मार्च तक पूरी करने की बात उन्होंने कही। रिनवा के अनुसार मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर दावा-आपत्ति और मैपिंग की प्रक्रिया जारी है। अब तक फार्म 7 के कुल 82 हजार 684 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि फार्म 6 के अनुसार 37 लाख 80 हजार 414 आवेदन आए हैं। फार्म 6 के आवेदन लगातार बढ़ने की बात भी उन्होंने कही है। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया के दौरान लगभग एक करोड़ 4 लाख मतदाता ऐसे पाए गए, जिनमें तार्किक विसंगति थी और इन्हीं के कारण उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया और अब इन्हीं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। रिनवा ने यह भी बताया कि कुल 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जाने हैं, जिनमें से अब तक 2 करोड़ 37 लाख नोटिस जनरेट हो गए हैं, इनमें से 86 लाख मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 30 लाख 30 हजार मतदाताओं की सुनवाई पूरी कर ली गई है। एसआईआर का काम पूरे जोरो-शोरों से चल रहा है, लेकिन साथ-साथ विवाद भी चल रहा है। जहां चुनाव आयोग बराबर दावा कर रहा है कि कोई भी पात्र उम्मीदवार नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं तमाम विपक्षी नेता चुनाव आयोग की नीयत पर संदेह जता रहे हैं और वह साफ कह रहे हैं कि एसआईआर का असली मकसद नाम जोड़ना नहीं बल्कि नामों में कटीती करना है। यह देखना किसी विडंबना से कम नहीं है कि कोई भी पक्ष इस संबंध में अपने स्टैंड से पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम विपक्षी नेता जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नाम शामिल हैं, खुलकर चुनाव आयोग की आलोचना कर रहे हैं और उसको भाजपा का एजेंट तक कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की संहत पर किसी तरह का कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है और वह अपने काम को अपने तरीके से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि मतदाताओं की जो लिस्ट बने वह पारदर्शी और निष्पक्ष हो और उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं दिखाई देना चाहिए, तो वहीं चुनाव आयोग का यह भी दायित्व बनता है कि वह सत्ता पक्ष व विपक्ष को समान रूप से साथ लेकर आगे बढ़े। अगर एक पक्ष को उस पर विश्वास नहीं होगा, तो फिर चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठेगा और जब सवाल उठेंगे तो लोगों के मन में भी संशय पैदा होगा। ऐसे में यह काम मनमानी से नहीं बल्कि सहमति के आधार पर होना चाहिए।

ब्राह्मण समाज का अपमान और अनादर

फिल्म घूसखोर पंडित में पंडित शब्द को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी बेहद दुखद और चिंताजनक है, अब फिल्मों के माध्यम से भी एक विशेष वर्ग का अपमान किया जा रहा है, जिससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है, फिल्म में पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान और अनादर किया गया है, इस तरह की जातिसूचक टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली हैं और इन्हें किसी भी सूत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता, बसपा इस तरह की टिप्पणी की कड़ी निंदा करती है, ऐसी जातिसूचक और समाज को बांटने वाली फिल्म पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाए, किसी भी माध्यम से किसी समाज को अपमानित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक समरसता के लिए भी घातक है।

—**सुश्री मायावती, अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी**



भारतीय न्यूज चैनलों का भविष्य क्या दांव पर लग चुका है? बड़ी संख्या में न्यूज चैनलों से दर्शक विमुख हुए हैं। तमाम दर्शकों ने विगत कुछ सालों से न्यूज चैनलों को आंख तक नहीं लगाया है। मात्र 25 सालों में ही न्यूज चैनल अपनी विश्वसनीयता और अपना विशालकाय दर्शक वर्ग खो देंगे, ऐसा नहीं सोचा गया था लेकिन यह हो चुका है। न्यूज चैनल्स के दर्शक अब सिर से गायब हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है चीनलों का जनसरोक़। री खबरों से दूर होना और पूरा दिन सांप्रदायिक बहसों को हवा देना। दरअसल, भारतीय चैनल्स एक्सपो हो चुके हैं और यह प्रकृति का नियम है कि जो एक बार एक्सपोज हो जाता है वह हमेशा के लिए हाशिए पर चला जाता है। विश्वसनीयता का धूलधूसरित होना न्यूज चैनलों के विनाश का प्रमुख कारण बन रहा है। एक उदाहरण देना चाहूंगा जैसे ही दिल्ली के एक बड़े हिंदी न्यूज चैनल को एक विशालकाय उद्योगपति ने टैक ओवर किया, उसके कुछ ही महीनों बाद चैनल का एक बड़ा दर्शक वर्ग उस चैनल से भाग खड़ा हुआ। अब हुआ यह कि चैनल संचालक जनता से दूर हटे और जनता उनसे दूर हुई। आप न्यूज चैनल तो खोल सकते हैं, लेकिन दर्शक वर्ग किसी भी कीमत पर नहीं ला सकते। आज हालात यह हो चले हैं कि तमाम न्यूज चैनलों ने अपने-अपने ब्राड कास्टिंग लाइसेंस सेरेंडर करने आरंभ कर दिए हैं। यह सब मात्र ढाई दशकों में ही देखने को मिलेगा ऐसा नहीं सोचा था। देश में विगत तीन वर्षों में करीब 50 टीवी चैनलों ने अपने ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस सेरेंडर कर दिए हैं।

लगातार एक ही तरह की प्रायोजित और एक तरफा खबरों से उकताए दर्शकों का एक बड़ा वर्ग डिजिटल व OTT प्लेटफॉर्म की ओर जा चुका है। इसके बाद चैनल आपटरों को दूसरा झटका गिरते विज्ञापन राजस्व, उच्च परिचालन लागत और बाजार की बदलती हुई स्थितियों ने दिया। परिचालन लागत ज्यादा हुई व विज्ञापन राजस्व कम हुआ। साथ ही दर्शक वर्ग गायब और कम दर्शकों के कारण विज्ञापन दाता कंपनियों द्वारा हाथ खींचना या विज्ञापन दरें कम कर देना, एक बड़ा कारण रहा। यह अस्सर इंटरनेट चीनलों पर भी देखा जा रहा है। देश में DTH ग्राहकों में भी लगातार भारी गिरावट होती जा रही है। भारत में DTH ग्राहकों की संख्या वित्तीय वर्ष 2019-20 में 72 मिलियन से घटकर वित्तीय वर्ष 2024 में 62 मिलियन रह गई। यह संख्या लगातार तेजी से घटती जा रही है। विगत वर्षों में जिन प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स ने अपने-अपने लाइसेंस सेरेंडर किए

चैनलों का खेल खत्म, सरेंडर हो रहे हैं लाइसेंस



हैं उनमें-JioStar, Zee Entertainment, Eenadu Television, TV Today Network, NDTV और ABP छमजूवता के नाम शामिल हैं जिन्होंने अपने कई चैनलों के लाइसेंस सेरेंडर कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार CulverMa Entertainment यानी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने भी 26 डाउनलिकिंग अनुमतियां सेरेंडर की हैं। ABPNetwork ने उच्च लागत के कारण ABPNews HD बंद कर दिया और NDTV ने अपने प्रस्तावित NDTV Gujarati चैनल का लाइसेंस वापस कर दिया। न्यूज चैनल्स जो कभी धड़ाधड़ प्रादेशिक न्यूज चैनल्स खोल रहे थे वह सब के सब धीरे-धीरे बंद होते चले गए। सबसे ज्यादा प्रादेशिक चैनल्स बंद हुए। मेरे एक पत्रकार साथी ने 2016 में बातचीत में कहा था कि एक दिन लाल किले के पीछे बाजार में न्यूज चैनलों के कैमरे और आईडी किलो में बिकेंगे। वह बात

आज सच साबित हो रही है। जो न्यूज चैनल्स जिंदा भी हैं उनको विभिन्न राज्यों के सूचना विभाग और दिल्ली की मिनिस्ट्री आफ ब्राड कास्टिंग ने वेंटीलेटर की सुविधा पर रख रखा है। नाम न खोलने की शर्त पर एक बड़ी कंपनी के सीईओ जो कि मेरे मित्र भी हैं, का कहना है-हर साल हमारी कंपनी का पब्लिसिटी बजट करीब 20 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से आम जनता की पर्चेजिंग पावर घटी है और निर्यात में दिक्कतें बढ़ी हैं, अब पब्लिसिटी बजट जारी रख पाना कठिन है। चीन से जबरदस्त चुनौती अलग से है। कर्माबेश देश की तमाम बड़ी कंपनियों ने अपना पब्लिसिटी बजट घटा दिया है और अब अपनी शर्तों पर विज्ञापन जारी कर रही हैं। उनके रेट पर विज्ञापन लेना हो तो आओ वरना चैनल के आफिस में बैठो। न्यूज चैनल्स के संदर्भ में हालात अभी और भी खराब होंगे। दर्शकों को

जलवायु परिवर्तन: आल्पस में भूकंप का खतरा

1960 के दशक में जब मॉन्ट ब्लांक टनल बनाई जा रही थी तो पहाड़ों के भीतर से अचानक तेजी से बहता हुआ बिलकुल ताजा पानी मिला। यह पानी इतना ताजा था कि उसमें अभी तक चट्टानों के खनिज भी नहीं घुल पाए थे। हालांकि, कुछ वैज्ञानिकों ने इन निष्कर्षों पर थोड़ी सावधानी बरतने की बात कही है। वैज्ञानिक फिलिप वर्नाट का कहना है कि वैसे तो आंकड़े काफी मजबूत हैं लेकिन यह भी मुमकिन है कि मॉन्ट ब्लांक सुरंग बनाने के प्रभाव देर से सामने आ रहे हों। इसलिए जरूरी है कि इस तरह की घटनाओं पर लंबे समय तक अध्ययन किए जाएं ताकि पता चल सके कि ऐसा पैटर्न केवल आल्पस में है या दुनिया के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी है।

हम अक्सर सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण लू, बाढ़, जंगलों में आग और समुद्र स्तर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इसका एक और चौंकाने वाला असर पता चला है-आल्प्स पर्वतों में ग्लेशियरों के पिघलने से भूकंप का खतरा बढ़ सकता है। ऐसी घटना फ्रांस के मॉन्ट ब्लांक इलाके के एक ऊंचे बर्फ से ढंके पर्वत ग्रांड जोरासेस में घटी है। 2015 में जब इस क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ी तो भारी मात्रा में बर्फ पिघली।

इसके तुरंत बाद पहाड़ के नीचे छोटे-छोटे भूकंप महसूस किए गए। कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे छोटे-छोटे भूकंप कभी-कभी बड़े भूकंप की चेतावनी भी होते हैं, लेकिन बर्फ के पिघलने से भूकंप कैसे आ सकते हैं? जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी चट्टानों की दरारों से गहराई तक चला जाता है। वहां यह पानी चट्टानों पर दबाव बनाता है और जमीन के अंदर जो फॉल्ट लाइनें होती हैं, उनकी पकड़ कमजोर कर देता है। इन फॉल्ट लाइनों के फिसलने से ऊर्जा निकलती है जो भूकंप का कारण बनती है। ऐसा नहीं है कि यह प्रक्रिया सिर्फ आल्प्स में होती है। वैज्ञानिकों ने ताइवान जैसे इलाकों में भी देखा है कि बारिश के हिसाब से भूकंप की संख्या बदलती है। इसी तरह, जहां फ्रॉकिंग (तेल और गैस निकालने की प्रक्रिया) या जियोथर्मल ऊर्जा के लिए जमीन के भीतर दबाव के साथ पानी डाला जाता है, वहां भी छोटे भूकंप आ सकते हैं। ETH ज्यूरिख के वैज्ञानिकों द्वारा मॉन्ट

ब्लांक इलाके में छोटे भूकंप को मापने वाले यंत्रों की मदद से 2006 से अब तक दर्ज 12,000 से ज्यादा छोटे-छोटे भूकंपों के विश्लेषण से पता चला है कि 2015 की गर्मी के बाद इन भूकंपों की संख्या बढ़ी थी। यही पैटर्न अगले साल की ग्रीष्म लहरों के बाद भी दिखे। दिलचस्प बात यह है कि सतह के पास वाले छोटे भूकंप गर्मी के लगभग एक साल बाद बढ़े, जबकि गहराई (लगभग 7 कि.मी.) में आने वाले भूकंप दो साल बाद बढ़े। इसका कारण यह हो सकता है कि पानी को गहराई तक पहुंचने में समय लगता है। भूकंप संम्बंधी ऐसे अनुभव पहले भी हुए हैं।

1960 के दशक में जब मॉन्ट ब्लांक टनल बनाई जा रही थी तो पहाड़ों के भीतर से अचानक तेजी से बहता हुआ बिलकुल ताजा पानी मिला। यह पानी इतना ताजा था कि उसमें अभी तक चट्टानों के खनिज भी नहीं घुल पाए थे। हालांकि, कुछ वैज्ञानिकों ने इन निष्कर्षों पर थोड़ी सावधानी बरतने की बात कही है। वैज्ञानिक फिलिप वर्नाट का कहना है कि वैसे तो आंकड़े काफी मजबूत हैं लेकिन यह भी मुमकिन है कि मॉन्ट ब्लांक सुरंग बनाने के प्रभाव देर से सामने आ रहे हों। इसलिए जरूरी है कि इस तरह की घटनाओं पर लंबे समय तक अध्ययन किए जाएं ताकि पता चल सके कि ऐसा पैटर्न केवल आल्प्स में है या दुनिया के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी है। अभी तक तो आल्प्स में आए इन भूकंपों से मॉन्ट ब्लांक सुरंग या आस-पास के शहरों को कोई खतरा नहीं है। इस क्षेत्र की इमारतें रिक्टर पैमाने पर 6 स्तर के भूकंप



झेलेने लायक बनाई गई हैं, लेकिन स्थिति हिमालय जैसे इलाकों में ज्यादा गंभीर हो सकती है, जहां ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और जहां बड़े और खतरनाक भूकंप आने की आशंका भी ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन बढ़ता जा रहा है और यह अध्ययन हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती पहले से ही एक नाजुक हालत में हैय ग्लेशियर पिघलने जैसे छोटे बदलाव भी इसे और अस्थिर कर सकते हैं।

—**स्रोत फीचर्स**

आकस्मिक चिकित्सा सुविधाओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता

जब सिर्फ पैसों के कारण आपात स्थिति में इलाज नहीं दिया जाता, तो कई बार जान चली जाती है। यह लेख ऐसे ही कुछ बेहद जरूरी मामलों को सामने लाता है और सख्त निरम्यां और उन्हें सही तरीके से लागू करने की मांग करता है, ताकि संकट के समय किसी को भी इलाज से वंचित न किया जाए। कुछ ही महीने पहले पुणे में एक बहुत दुखद घटना घटी। एक गर्भवती महिला, जिसे पहले से ही गंभीर स्थिति में माना गया था और जो समय से पहले जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी, उसे पुणे के जाने-माने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज शुरू करने के लिए अस्पताल ने 10 लाख रुपए एडवांस जमा करने की मांग की।

परिवार ने इलाज के लिए गुहार लगाई और भरोसा दिलाया कि थोड़ी देर में पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन अस्पताल ने पैसे के बिना इलाज शुरू करने से मना कर दिया। इससे कोमती समय बर्बाद हुआ और महिला को दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां उसने जुड़वां लड़कियों को जन्म तो दिया, लेकिन उसकी खुद की जान नहीं बच सकी।

बेवजह देरी— जप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब मातुत्व मृत्यु रोकने की बात होती है, तो अक्सर श्री डिले मॉडल (तीन देरिया) का जिक्र होता है। इस मॉडल से यह समझने में मदद मिलती है कि इलाज में किस-किस स्तर पर होने वाली देरी मा की जान ले सकती है। सबसे पहली देरी होती है घर में—जब परिवार यह तय करने में समय लगाता है कि इलाज करवाना है या नहीं। दूसरी



देरी होती है अस्पताल तक पहुंचने में—जब रास्ते की दूरी, खराब सड़कें या परिवहन की समस्या आड़े आती है। तीसरी देरी तब होती है जब मरीज अस्पताल पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां स्टॉफ की कमी, जरूरी साधनों के अभाव या तंत्र की लापरवाही के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता। हालांकि यह मॉडल आम तौर पर गर्भवती महिलाओं के इलाज के संदर्भ में लागू किया जाता है, लेकिन इसे हर उस आपात स्थिति पर लागू किया जा सकता है जहां समय पर इलाज न मिलने से मरीज की जान जा सकती है।

हमारे देश में तीसरे प्रकार की देरी से होने वाली मौतें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखी जाती हैं, जहां न तो अस्पताल होते हैं और न ही स्टॉफ। लेकिन यह मामला एक चौंकाने वाला शहरी उदाहरण है, जहां देरी

का कारण सुविधाओं की कमी नहीं, बल्कि निजी अस्पतालों की कॉर्पोरेट सख्ती था। यह जानते हुए भी कि महिला की हालत बेहद गंभीर थी, अस्पताल ने सिर्फ पैसों की वजह से इलाज करने से मना कर दिया। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बात को सामने लाएं कि जो बड़े निजी अस्पताल सरकारी छूट और सुविधाएं लेते हैं, वे आपात स्थिति में जरूरतमंद मरीजों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कैसे कई बार वित्तीय हित मरीज की देखभाल और सुरक्षा से ज्यादा अहम हो जाते हैं।

मेरा निजी अनुभव— उपरोक्त खबर को पढ़ने के बाद मुझे भी अपना एक हालिया अनुभव साझा करने की जरूरत महसूस हो रही है, जो यह दिखाता है कि निजी अस्पतालों में नीतियों में बदलाव और जवाबदेही कितनी जरूरी है।

मेरी पत्नी को एक्टोपिक प्रेग्नंसी जिसमें गर्भधारण गर्भाशय की बजाय किसी अन्य स्थान पर हो जाता है और यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी होती है की स्थिति में तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हमारे पास स्वास्थ्य बीमा था, इसलिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध थी। मैंने सारे जरूरी दस्तावेज तुरंत जमा कर दिए। बताया गया कि बीमा क्लेम की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मंजूरी में लगभग तीन घंटे लगेगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक 25,000 रुपए एडवांस में नहीं दिए जाते, सर्जरी शुरू नहीं होगी।

मेरे लिए पैसा देना मुश्किल नहीं था, फिर भी मैंने पूछा कि जब कैशलेस सुविधा है तो क्या पैसे मिलने के लिए तीन घंटे का इंतजार नहीं किया जा सकता? जवाब मिला कि सर्जरी तभी शुरू होगी जब कैशलेस क्लेम मंजूर हो जाएगा। मैंने बार-बार समझाया कि यह इमरजेंसी है, लेकिन बिलिंग विभाग ने कोई नरमी नहीं दिखाई। आखिरकार मैंने एडवांस राशि दी, सर्जरी हुई और जैसा अनुमान था, क्लेम भी मंजूर हो गया। पत्नी की छुट्टी के बाद जमा की गई राशि लौटा दी गई। लेकिन इस अनुभव ने मेरे जेहन में कई सवाल छोड़ दिए।

यदि उस समय मेरे पास 25,000 रुपए न होते तो क्या मेरी पत्नी की सर्जरी टल जाती, जबकि मैंने कैशलेस इलाज के लिए सारे जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे और यदि देरी से उनकी सेहत को नुकसान होता, तो उसका लिएम्पेदार कौन होता? आपात स्थिति में इन प्रक्रियाओं की बजाय अस्पताल इलाज को प्राथमिकता क्यों नहीं देते? जब मरीज को सर्जरी या गंभीर इलाज

की जरूरत है और वह 2.3 दिन अस्पताल में रहने वाला है, और 25,000 रुपए की एडवांस राशि बहुत बड़ी नहीं है, खासकर तब जब अस्पताल कैशलेस सुविधा वाला है और बीमा से पैसा मिलना ही वाला है। फिर भी इलाज शुरू करने से पहले इतनी बेरहमी से एडवांस की मांग क्यों? इलाज में देरी जान ले सकती है। क्या ऐसी स्थिति में ईसानियत और सहयोग की भावना जरूरी नहीं है? आपात समय में मरीज के परिवारजन घबराए होते हैं और कभी-कभी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है।

ऐसे मौकों पर क्या अस्पताल को थोड़ी नरमी नहीं दिखानी चाहिए? मरीज की जान से जुड़ी स्थिति में अस्पताल इतनी कठोर नीति क्यों अपनाते हैं? और आखिर किसने निजी अस्पतालों को यह हक दिया कि वे मरीज की जान को इस तरह जोखिम में डालें? वैसे कैशलेस क्लेम को मंजूरी मिल गई थी, और जो पैसे मैंने एडवांस में दिए थे, जो पैसे मुझे तुरंत नहीं मिले थे। यहां मुझसे एक ग्राहक के तौर पर उम्मीद की गई थी कि मैं अस्पताल की आंतरिक प्रक्रिया के साथ सहयोग करूँ। लेकिन क्या अस्पतालों द्वारा एडवांस राशि तुरंत जमा करवाने के नियम में ढील नही दी जानी चाहिए, खासकर इमर्जेंसी की स्थिति में? क्या मरीज के परि. जनों की यह उम्मीद गलत है कि ऐसी स्थिति में अस्पताल थोड़ा लचीलापन दिखाए? यहां साफ तौर पर असंतुलन हैय जहां मरीज से तो उम्मीद की जाती है कि वह अस्पताल की प्रक्रियाओं का सम्मान करें, लेकिन अस्पताल मरीज की जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है।

—**साभार एस.एफ**

